भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1761

जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है

राजमार्गों पर जीपीएस टोल

1761. श्री इमरान मसूद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में वाहनों में जीपीएस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण हेतु नई प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चंडीगढ़-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-73 मार्ग पर यात्रियों को अनुचित पथकर का भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जबकि सरसावा टोल प्लाजा के दोनों ओर के टोल प्लाजाओं के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उक्त पथकर प्लाजा को गैर-कानूनी मानते हुए इसे बंद करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में पायलट अध्ययन पहले ही निम्नलिखित दो राजमार्ग खंडों पर किया जा चुका है: -

(i) कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-275 का बेंगलुरु-मैसूर खंड।

(ii) हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-709 (पुराना रारा-71ए) का पानीपत-हिसार खंड।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभ में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) प्रणाली को पायलट आधार पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंडों पर लागू किया जाएगा।

(ख) 60 किलोमीटर की सीमा के भीतर कार्यरत शुल्क प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार भी अनुमत हैं। चंडीगढ़-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग -73 पर सरसावा प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों प्रावधान के संदर्भ में भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना संख्या 3217 (अ) दिनांक 22 सितंबर, 2020 के अनुसार संग्रहित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*****